

राजस्थान में पाइराइट के भण्डार

517. श्री जगदीश प्रसाद माथुर :

या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान स्थित सोलतिपुरा में पाइराइट के भण्डारों का पता चला है ,

(ख) इनके उत्खनन के लिए अब तक क्या प्रबन्ध किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकार द्वारा खान के स्थान पर जो बिजली दी जा रही है वह अपर्याप्त है और बिजली के बार-बार बन्द हो जाने से खान के कार्य में बाधा पड़ती है, यदि हां, तो इस प्रबन्ध में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

(घ) क्या यह सच है कि खनिज विभागों ने रेलवे विभाग से इस स्थान तक रेल की पटरी विछाने के लिए कहा है ; और ,

(ङ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†[PYRITE DEPOSITS IN RAJASTHAN

517. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of STEEL AND MINES/

इस्पात और खान मंत्री

be pleased to state:

(a) whether it is a fact that pyrite deposits have been found at Solitipura in Rajasthan;

(b) what arrangement has so far been made for its mining;

(c) whether it is a fact that the power which has been under available at the site of the mine by the State Government is inadequate and fre-

quent power failures hamper the working of the mine, if so, what measures have been taken to improve this arrangement;

(d) whether it is a fact that Minerals Departments have urged the Railway Department to lay a railway line upto the said place; and

(e) if so, the details thereof?]

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां, राजस्थान के सलादीपुर में पाइराइट्स का वृहद् निक्षेप पाया गया है ।

(ख) भारत सरकार के उपक्रम पाइराइट्स, फास्फेट्स और रसायन लिमिटेड ने सितम्बर, 1969 से समन्वेषी-सह-उत्पादन खनन प्रारम्भ किया है, जिसके लिए 82 लाख रुपयों की लागत पर परियोजना मंजूर की गई थी । इस निक्षेप के वाणिज्यिक समुप-योजन के लिए विस्तृत खनन प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

(ग) विद्युत्-प्रदाय अपर्याप्त नहीं है लेकिन विद्युत-प्रदाय में कुछ बार-बार अवरोधन हुए हैं । राज्य विद्युत बोर्ड विद्युत-प्रदाय की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है और आशा की जाती है कि विद्युत-प्रदाय में सुधार होगा ।

(घ) और (ङ) रेल प्राधिकारियों से रेलवे साईडिंग का सर्वेक्षण करने के लिए अनुरोध किया गया था, जिसे सम्पूरित किया जा चुका है । रेल विभाग से अनुमान प्रतीक्षित है ।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES/

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री

(SHRI SHAH NAWAZ KHAN):

(a) Yes, Sir, a large deposit of pyrite has been found at Saladipura in Rajasthan.

(b) A Government undertaking, Pyrites, Phosphates & Chemicals Ltd. has started exploratory cum production mining since September, 1969, for which a scheme costing Rs. 82 lakhs was sanctioned. A detailed mining project report is going to be prepared for the commercial exploitation of this deposit.

(c) The power supply is not inadequate but there has been some frequent interruptions in power supply. The State Electricity Board is taking necessary steps to improve the power supply and it is expected that there will be improvement in power supply.

(d) and (e) The Railway authorities were requested to conduct a survey for Railway siding, which has been completed. The estimates are awaited from the Railways.]

सिंचाई के लिये भूमिगत जल

518. श्री सुरज प्रसाद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सिंचाई के प्रयोजनार्थ भूमिगत जल का उपयोग करने की योजनाओं को किन किन राज्यों में आरम्भ किया जा चुका है ; और

(ख) सरकार द्वारा इस प्रकार की परियोजनाएं अन्य राज्यों में भी क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

[†UNDERGROUND WATER FOR IRRIGATION PURPOSES

518. SHRI SURAJ PRASAD : Will the Minister of AGRICULTURE

कृषि मंत्री

be pleased to state:

(a) the names of the States where

the Schemes for using underground water for irrigation purposes have been undertaken by Government; and

(b) what action is being taken by Government to implement such projects in other States also?]

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) लगभग सभी राज्यों में क्षेत्रीय औचित्यों के अनुसार भूमिगत जल उपयोगी योजनाओं को, जिनमें सिंचाई के लिए खुदाई के कुएं, उथले नलकूप आदि जैसे गैर सरकारी निर्माण-कार्य शामिल हैं, तकावी ऋण और सस्थात्मक ऋण द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जम्मू और काश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में गहरी सतहों में विद्यमान जल को काम में लाने और उन किसानों को जो कि अपने निजी नलकूप अथवा कुओं का व्यय वहन नहीं कर सकते, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए सरकारी नलकूपों का भी निर्माण किया जा रहा है।

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से इस बात की जोरदार मिफारिश करती रही है कि जहां कहीं नलकूपों का निर्माण सम्भव हो, वहां राज्य योजनाओं के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में नलकूपों का निर्माण कार्य को प्राथमिकता प्रदान की जाये।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री

(PROF. SHER SINGH): (a) Groundwater utilisation schemes consisting of private works like dugwells, shallow tubewells etc. for irrigation purposes are being encouraged through taccavi loans and institutional credit in nearly all the States, in